भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1632

जिसका उत्तर मंगलवार 08 मार्च, 2016 को दिया जाना है

औद्योगिक क्षेत्र का मूल्यांकन

1632. श्री पशुपति नाथ सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों में देश में पूंजीगत वस्तुएं, ऑटो और इलेक्ट्रिक उपकरण क्षेत्र के विकास और वृद्धि हेतु कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में उक्त क्षेत्रों के विकास और वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत ग. गीते)

(क): केपिटल गुड्स सेक्टर पिछले तीन वर्षों के दौरान, 1.1% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा है। वर्ष 2014-15 के दौरान केपिटल गुड्स के चुनिंदा उप-सेक्टरों का उत्पादन, आयात तथा निर्यात का मूल्य और 5 वर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

केपिटल गुड्स के उप सेक्टर	उत्पादन (5 वर्ष सीएजीआर)	आयात (5 वर्ष सीएजीआर)	निर्यात (5 वर्ष सीएजीआर)
मशीन टूल	4,230 (I1.2%)	5318 (1.9%)	28I (18.2%)
वस्त्र मशीनरी	6,960 (10.4%)	7,814 (16%)	2,466 (34.7%)
अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी	I 7,000 (0.6%)	12,056 (16.4%)	7,385 (55.3%)
हेवी इलेक्ट्रिकल उपकरण	1,36953 (6.6%)	55,987 (6.4%)	35,418 (14%)
प्लास्टिक मशीनरी उपकरण	2,950 (9.6%)	1,350 (10.7%)	680 (11.6%)
प्रोसेस प्लांट उपकरण	18,900 (3.4%)	12,933 (120.9%)	7,684 (23.3%)
डाई, सांचे और प्रेस उपकरण	14,647 (5.1%)	3,322 (-2.4%)	2,869 (-3.8%)
धातुकर्म मशीनरी	1,260 (5.0%)	2,593 (-4.4%)	1,103 (20.1%)
प्रिंटिंग मशीनरी	14,453 (14.4%)	6,38I (12.2%)	1,255 (13.9%)
खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	12,180 (6.2%)	5,500 (5.5%)	2,080 (15.8%)
कुल	**229,533** (6.2%)	**113,254** (9.8%)	**61,221** **(16.5%)**

(स्रोत: राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति 2016)

ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए 2013-14 और 2014-15 में (घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों आंकड़ों सहित) उद्योग का कारोबार क्रमशः ₹3,55,442 करोड़ और ₹3,83,730 करोड़ है। ऑटोमोबाइल कलपुर्जों के लिए उद्योग का कारोबार 2013-14 और 2014-15 के लिए क्रमशः ₹2,11,700 करोड़ और ₹2,34,800 करोड़ है।

(स्रोत: सिआम एवं एक्मा)

(ख): जी, हां। सरकार ने केपिटल गुड्स सेक्टर के विकास और वृद्धि के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है।

भारतीय इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग के लिए सरकार ने भारतीय इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग मिशन प्लान 2012-22 तैयार किया है जिसे घरेलू इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग की वृद्धि में गति लाने तथा उस वृद्धि को बरकरार रखने के लिए सभी हितधारकों के प्रयासों का संचालन, समन्वय और उन प्रयासों के बीच तालमेल कायम करने के उद्देश्य से 24.07.2013 को शुरू किया गया था।

ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, सरकार ने ऑटमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) अर्थात् एएमपी 2006-16 तैयार किया। इसके बाद एएमपी 2016-26 आएगा।

(ग): राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति

सरकार ने केपिटल गुड्स संबंधी मुद्दों, चुनौतियों का समग्र रूप से निवारण करने और 'मेक इन इंडिया' अवसरों का लाभ उठाने के लिए भी एकीकृत राष्ट्रीय गुड्स नीति की शुरुआत की है। यह नीति इस दृष्टिकोण से तैयार की गई है कि कुल विनिर्माण क्रियाकलापों में केपिटल गुड्स का योगदान जो फिलहाल 12% है, उसमें वृद्धि करते हुए 2025 तक 20% किया जाए। राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति में केपिटल गुड्स वृद्धि के लिए समर्थकारी माहौल उपलब्ध कराते हुए तथा घरेलू और निर्यात बाजार मांग को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी मशीनरी का विनिर्माण करने हेतु घरेलू विनिर्माताओं के लिए सतत प्रोत्साहन सुनिश्चित करते हुए केपिटल गुड्स सेक्टर को बढ़ावा देने के प्रयास करने की परिकल्पना की गई है।

नीति की मुख्य सिफारिश है कि विभाग द्वारा नवम्बर, 2014 में आरंभ की गई मौजूदा केपिटल गुड्स स्कीम को सुदृढ़ किया जाए जिसमें प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्र, साझा इंजीनियरी सुविधा केन्द्र आदि के दायरे एवं बजटीय आबंटन में बढ़ोतरी करना, प्रौद्योगिकी विकास निधि आरंभ करना, 'केपिटल गुडस सेक्टर के लिए स्टार्ट-अप केन्द्र' बनाना, अनिवार्य मानकीकरण, विकास का उन्नयन, परीक्षण एवं प्रमाणन अवसंरचना, कौशल विकास, क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से वृद्धि संवर्धन की स्कीम उपलब्ध कराना, केपिटल गुड्स की मौजूदा इकाइयों का आधुनिकीकरण तथा भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता स्कीम के लिए एक समर्थकारी प्रायोगिक स्कीम का सृजन करने जैसे घटक शामिल हैं। नीति का विवरण भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

इलेक्ट्रिकल उपकरण सेक्टर से संबंधित नीति:

इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग के लिए भारतीय इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग मिशन प्लान 2012-2022 में व्यक्त विजन 2022 में इलेक्ट्रिकल उपकरण के उत्पादन के संबंध में भारत को पसंदीदा देश बनाना और निर्यातों तथा आयातों का संतुलन कायम करते हुए उत्पादन 100 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचाना शामिल है। मिशन प्लान में कार्यान्वयन के पांच प्रमुख क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं, (i) उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता; (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन; (iii) कौशल विकास; (iv) निर्यात् और (v) अप्रकट मांग का प्रकट मांग में परिवर्तन।

सरोकार के प्रत्येक क्षेत्र में, सरकार और उद्योग सहित अलग-अलग हितधारकों द्वारा रणनीतिक और नीतिगत उपायों के लिए सिफारिशें विस्तारपूर्वक दी गई हैं । मिशन प्लान 2012-2022 का ब्यौरा भारी उद्योग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

मिशन प्लान की शुरूआत के पश्चात् प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत संस्तुत विभिन्न उपाय करने के लिए निश्चयात्मक तथा आम दृष्टिकोण तैयार करने के लिए दो अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) स्थापित किए गए हैं।

ऑटो सेक्टर से संबंधित नीति और स्कीमें:

भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए **ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) 2006-16** का विजन है कि ऑटोमोबाइल तथा ऑटो कलपुर्जों के डिजाइन और विनिर्माण के संबंध में भारत को विश्व के पसंदीदा गन्तव्य के रूप में उभारते हुए उत्पादन को वर्ष 2016 तक 145 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक ले जाकर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक किया जाए और 25 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। एएमपी 2006-16 की प्रचालन अवधि के दौरान, देश ने ऑटोमोटिव सेक्टर में खासी प्रगति की जब विश्व के प्रमुख मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) ने भारत में अपनी विनिर्माण इकाइयों को स्थापित किया और बाजार को विविध प्रकार के वाहनों से सराबोर किया। इस अवधि के दौरान, ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश ₹1,60,000 करोड़ से अधिक हो गया। भारत विश्व स्तर पर छोटी कार विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ। एएमपी 2006-2016 के ब्यौरे भारी उद्योग की वेबसाइट (dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

एएमपी 2016-26: मिशन प्लान-एएमपी 2016-26 को एएमपी-2006-16 में परिकल्पित प्रयासों को जारी रखने के विचार से तैयार किया गया है। एएमपी 2016-26 का विजन है कि भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग वाहनों और कलपुर्जों की इंजीनियरी, विनिर्माण और निर्यात में विश्व के शीर्ष तीन देशों में शामिल हो और वैश्विक मानकों के अनुरूप लोगों को किफायती आवाजाही और माल के परिवहन के लिए सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं। एएमपी 2016-26 ऑटो सेक्टर में भारत की जीडीपी के 12% से अधिक मूल्य की वृद्धि और 65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजन की परिकल्पना करता है। एएमपी 2016-26 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(क) भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को शीर्ष रोजगार सृजनकर्ता बनाना- 65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार।

(ख) भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को विनिर्माण सेक्टर और 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का मुख्य चालक बनाना।

(ग) ऑटोमोटिव उद्योग का लक्ष्य है कि वाहनों के निर्यात् को 5 गुणा और कलपुर्जों के निर्यात् को 7.5 गुणा बढ़ाया जाए।

(घ) विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने और उसमें सुधार लाने तथा पर्यावरण एवं सुरक्षा की चुनौतियों का निवारण करने के लिए विशिष्ट उपाय परिकल्पित हैं।

एएमपी 2016-26 शीघ्र ही शुरू किए जाने के लिए तैयार है।

******